which does not exceed Rs. 2500/—p.m. should be made only through National Employment Service. Other sources of employment for such posts can be tapped only if the Employment Exchanges issue Non-availability Certificate to this effect.

(b) According to available information, no such complaint has been received.

(c) Docs not arise.

गरीबी उन्मूलन के लिये गये विभागों की स्थापना

*318. **चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन से संबंधित स्थापित किये गये नये विभागों का गरीब वर्गो के लाभर्थियों पर कोई खास प्रभाव पड़ा है, और

(ख) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में नौकरशाही के कारण होने वाले विलम्ब को कम करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) और (ख) नए विभागों के सृजन का उद्देश्य गरीबी उपशसन पर विशेष बल देते हुए उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि लक्षित समूहों को भरपूर लाभ मिल सके। गरीबी उपशमनर से संबंधित नव-सृजित विभाग विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था का तीवर विकास सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करके गरीबों पर अधिक ध्यान देने के लिए गरीबी पर सीधा और सामने से प्रहार करेंगे।

गरीबी उपशमन के कार्यो में लालफीताशाही समाप्त करने के लिए विगत में कोई कदम उठाए गए हैं। उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित कार्यान्वयन एंजेंसियों को सीधे निधियां रिलीज करना है। ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की सुव्यवस्थित स्थापना से यह आशा की जाती है कि लोगों की भागीदारी से ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में न केवल और भी तेजी लाई जाएगी बल्कि यह और भी प्रभावी हो सकेगा।

Service conditions for Nuclear Power Corporation employees.

*319. SHRI E. BALANANDAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the package of service conditions for the Nuclear Power Corporation employees has been finalised;

(b) whether any option is given to the employees to continue as indefinite deputationists without getting absorbed themselves in the Nuclear Power Corporation;

(c) if so, what are the facilities/ benefits extended/denied to those who opted to ramain as indefinite deputationists;

(d) whether the benefits denied to them include those available to them as Government servants, like promotion and such other service benefits; and

(e) if so, the reasons for denial of their rights as Central Government employees over and above violation of the terms contained in the Package Service Conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Employees who have opted to remain on indefinite deputation are governed by the service conditions as applicable to Central Government employees.

The following benefits, which were being enjoyed by the deputationists prior to the last date for exercising option i.e. 16.9.94 were sought to be withdrawn in respect of those who preferred to remain on indefinite deputation. But these are being continued in view of the orders to maintain status quo by the Central Administrative Tribunal.